(c) the amount of arrears outstanding?

The Minister of State in the Ministry of Food, Agriculture, Community Development and Cooperation (Shri Annasahib Shinde): (a) Yes, the matter is under consideration of Delhi Administration.

(b) No. As against an annual demand of Rs. 4 lakhs (approximately) the collections of land revenue, current and arrear, during the last two years amount to Rs. 21,59,874. The total collections during last 7 years amount to Rs. 31,91,182. Figures for the period prior to 1960 are not readily available.

(c) A sum of Rs. 18,89,652 is outstanding as arrears of land revenue as on 1-7-1967.

सामुदायिक विकास कार्य

*1667. **श्री सिद्धेश्वर प्रसाद** : क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) अधिकतर राज्यों में सामुदायिक विकास कार्यों के रुक जाने के क्या कारण हैं ;

(ख) इस स्थिति को सुधारने के लिये क्या कार्यवाही की जा रही है ; और

(ग) खण्ड कार्यालयों की व्यवस्था को सुधारने के लिए किन-किन राज्यों में कार्यवाही की गई है, तथा क्या कार्यवाही की गई है और उसका क्या परिणाम रहा है ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री एम० एस० गुरुपदस्वामी) : (क) सामुदायिक विकास कार्यक्रम में गतिरोध के मुख्य कारण कार्यक्रम प्राथमिकताओं में परिवर्तन, साधनों की कमी और अपेक्षित स्तरों की कुशलता तथा जानकारी वाली विस्तार सेवाओं की आनुपातिक अपर्याप्तता हो सकते हैं ।

(ख) सामुदायिक विकास संबंधी नीति के नये सूत्र, जो तैयार किए गए हैं और राज्य सरकारों को उनकी राय के लिए भेजे गए हैं, के अन्तर्गत कार्यक्रम की विषय-वस्तु को पुनर्व्यवस्थित किया गया है ताकि चालू प्राथमिकताओं से उनका ठीक प्रकार से तालमेल हो । ऐसा करते समय स्थानीय आवश्यताओं तथा साधनों का ध्यान का रखा गया है । कुल साधनों की सीमाओं के भीतर सामुदायिक विकास कार्यक्रम के लिए अधिकतम परिव्यय प्राप्त करने के लिए प्रयत्न जारी हैं । राज्य सरकारों से भी अनुरोध किया गया है कि वे दूसरी विभागीय योजनाओं को उनके साधनों सहित ज्यादा से ज्यादा रूप में खण्ड अभिकरण को सौंप कर खण्ड कार्यक्रमों को मजबूत बनाएं । विस्तार कार्यकर्ताओं की कार्य करने की क्षमता में सुधार करने के लिए प्रशिक्षण तथा शिक्षा के कार्यक्रम भी शुरू किए गए हैं ।

(ग) महाराष्ट्र, गुजरात, राजस्थान, आन्ध्र प्रदेश और मद्रास जैसे राज्यों ने खण्ड अधिकरण को प्रचुर कार्यक्रम उनके साधनों सहित सौंपने की दिशा में कदम उठाए हैं । सभी राज्यों में ग्राम सेवक प्रशिक्षण केन्द्रों के उन्नयन और विस्तार अधिकारियों तथा जिला में उच्च स्तरीय कर्मचारियों के लिए विशेष पाठ्यक्रम आयोजित करने के कार्य हाथ में लिए हैं । मोटे तौर पर, ये उपाय लाभकारी प्रभाव डालने वाले प्रतीत हुए हैं ।

दिल्ली में मैदे और सूजी का वितरण

*1668. **श्री हरदयाल देवगुण :**
श्री हुकम चन्द कछवाय :
श्री जगन्नाथ राव जोशी :
श्री रघुवीर सिंह शास्त्री :
श्री प्रकाशवीर शास्त्री :
श्री शिवकुमार शास्त्री :
श्री यशवन्तसिंह कुशवाह :

श्री रामावतार शर्मा :
श्री आत्म दास :
श्री महन्त दिग्विजय नाथ :
डा० सूर्य प्रकाश पुरी :

क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भारतीय खाद्य निगम ने दिल्ली में मैदे और सूजी के वितरण का काम 12 जुलाई, 1967 से दिल्ली प्रशासन को सौंप दिया है;

(ख) क्या यह भी सच है कि खाद्य निगम ने दिल्ली प्रशासन के साथ सलाह किये बिना ही 12 जुलाई और 19 जुलाई, 1967 के बीच की अवधि में दिल्ली में अनेक बड़ उपभोक्ताओं को सीधे ही ये वस्तुएं दे दी थीं, और

(ग) यदि हां, तो उसके क्या कारण है ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री अन्ना साहिब शिन्दे) :(क) जी नहीं। दिल्लीके राशन वाले क्षेत्र में 12 जुलाई, 1967 से मैदा और सूजी राशन वाली वस्तुएं घोषित कर दी गयी थीं। अतः उस तारीख से इन वस्तुओं के वितरण की जिम्मेदारी दिल्ली प्रशासन की हो गयी थी। भारतीय खाद्य नगम का दिल्ली प्रशासन को इन वस्तुओं के वितरण का कार्यभार सौंपने का प्रश्न ही नहीं उठता।

(ख) जी नहीं। तथापि, अधिक खपत करनेवाले कुछ उपभोक्ताओं ने 12 जुलाई के बाद रोलर आटा मिलों से मैदा और सूजी प्राप्त की थी। इस संबंध में भारतीय खाद्य निगम 12 जुलाई, 1967 से पहले निकासी आदेश जारी किये थे।

(ग) प्रश्न ही नहीं उठता।

Seed Farms in Punjab

*1669. **Shri Madhu Limaye:**
Shri S. M. Banerjee:
Shri George Fernandes:
Dr. Ram Manohar Lohia:
Shri S. M. Joshi:
Shri Kameshwar Singh:
Shri Nihal Singh:
Shri Sheopujan Shastri:

Will the Minister of **Food and Agriculture** be pleased to state:

(a) whether there is a proposal to convert 10,000 acres of waste land into a seed farm in Punjab with the help of the World Bank;

(b) whether this farm will be in the public sector or will be leased to the Birla Institute Farm;

(c) whether there is also a proposal to set up a public sector seed farm with the help of the Centre in Punjab; and

(d) if so, the details of the proposals referred to in parts (a) and (c) above?

The Minister of State in the Ministry of Food, Agriculture, Community Development and Cooperation (Shri Annasahib Shinde): (a) There is no such proposal under consideration at present.

(b) Does not arise.

(c) and (d). A proposal for setting up a Central State Farm in the Punjab on the lines of the Suratgarh farm, is under consideration.

न्यायालयों का कार्य प्रादेशिक भाषाओं में करवाया जाना

*1670. **श्री विभूति मिश्र :**
श्री क० ना० तिवारी :

क्या **विधि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि 14 अप्रैल,